Central Water Commission
WSE Dte.,
****

West Block II, Wing No-4
R. K. Puram, New Delhi – 66.

Dated 4.2.2019.

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings will be uploaded on the CWC website.

4.2.2019
SPA (Publicity)

Encl: As stated above.

Deputy Director, WSE Dte. 04/02/2019

Director, WSE Dte. 04/02/2019

For information to

Chairman CWC, New Delhi

Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.nic.in

O/C

News item/letter/article/editorial Published on 04.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

वाराणसी में गंगा सीवर के पानी से मुक्त होगी

वाराणसी, (भाषा): गंगा कार्य योजना की शुरुआत होने के तीन दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद इस वर्ष नवम्बर से पवित्र नदी में सीवेज का पानी नहीं जाएगा। गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 14 जून 1986 को वाराणसी में गंगा कार्य योजना की शुरुआत की थी। नितिन गडकरी के तहत आने वाले गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय और राष्ट्रीय गंगा स्वछता मिशन (एनएमसीजी) ने वाराणसी में सीवर के पानी के शोधन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

गौरतलब है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। एनएमसीजी के अधिकारियों ने बताया कि रमना के नजदीक 50 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र का काम करीब करीब पूरा हो गया है। उम्मीद है कि यह इस साल नवंबर तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा और 'अस्सी नाले' से निकलने वाले पानी का शोधन करेगा। इससे वाराणसी शहर के सीवर के गंदे पानी को गंगा में जाने से पूरी तरह से रोका जा सकेगा। शहर से रोजाना करीब 30 करोड़ लीटर सीवर का पानी निकलता है।

News item/letter/article/editorial Published on 04.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi) ✓
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

AI to help keep an eye on floodplain

ISRO Roped In; Drones, Satellite Imagery To Stop Dumping Of Debris Along Yamuna

Ritam.Halder@timesgroup.com

New Delhi: A report by an expert committee constituted by the National Green Tribunal says that drones, artificial intelligence and satellite imagery could be used to monitor the pollution level of Yamuna due to dumping of debris on the floodplain, especially in the Delhi portion.

To put a stop on encroachment of vacant land, Delhi Development Authority (DDA) has tied up with Indian Space Research Organisation's (ISRO) regional remote sensing centre. It is putting in place a computerised system to detect encroachment using satellite images provided by ISRO. If successful, the satellite imagery could also be used to monitor the Yamuna floodplain, said the report by the monitoring committee established by NGT to monitor the river cleaning operation.

"In addition, artificial intelligence, aerial mapping or drones can also keep a track of quantum and location of debris being dumped. The issue of monitoring encroachment of vacant land using satellite imagery was taken up with ISRO. DDA reported that an agreement was signed on July 6, 2018 and it will become operational by July 6, 2019," said the report accessed by TOI.

NGT chairperson Justice AK Goel had set up the committee in July 2018 to monitor the cleaning of the river. The committee includes former Delhi chief secretary Shailaja Chandra and retired expert member BS Sajwan.

The expert panel has also recommended that an awareness programme must be organised to make people realise the importance of the river as "it means nothing to the citizens as it is providing no opportunities for cultural activities, leisure or recreation".

"Efforts to convert the retrieved waste into agarbattis and other useful products would be promoted," the report said.

The committee also suggested that Delhi government should set up a consortium of NGOs and board members of Delhi Pollution Control Committee to jointly consider and approve small, innovative projects that could help reduce pollution. It also said that enforcement must be done to stop sale on the bridges, which leads to pollution of the river.

"Building awareness requires a beginning to be made with schoolchildren, which could be handled with political leadership as had been done in campaigns for firecrackers and environmentally-safe Holi colours," the report said.

File photo

DIRTY PICTURE: NGT's expert panel said an awareness programme must be organised to make people realise the importance of the river

News item/letter/article/editorial Published on 04.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi) ✓
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

राजधानी में इस हफ्ते तीन दिन बारिश के आसार

H-4

मौसम का मिजाज

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते तीन दिन दिल्ली में बारिश हो सकती है। इससे सर्दी बढ़ सकती है। उधर, लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह घने कोहरे का सामना करना पड़ा।

सुबह 7:30 बजे मौसम विभाग के पालम केन्द्र में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रह गई थी। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 5 बजे से ही कोहरे की चादर घनी होनी शुरू हो गई। जबकि, पालम में 7:30 बजे के लगभग दृश्यता का स्तर सबसे कम रहा। सफदरजंग में दृश्यता का स्तर 500 मीटर तक दर्ज किया गया।

कोहरा कम होने के आसार : घने कोहरे से लोगों को सोमवार से छुटकारा मिल सकता है। सुबह कोहरा पड़ने के आसार हैं, लेकिन उसकी सघनता का स्तर कम रहेगा। वहीं, कोहरे से सूरज की चमक भी फीकी हो गई है। इससे लोगों को ठंड से भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह 6, 7 और 8 फरवरी को बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी बढ़ेगी। रविवार दिन में सफदरजंग मौसम केन्द्र में अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

सर्द मौसम में रविवार को इंडिया गेट के पास राजपथ पर घूमती बच्चियां। • सोनू मेहता

तेज हवा से वायु गुणवत्ता में सुधार

राजधानी में हवा की गति में बढ़ोत्तरी से वायु गुणवत्ता में सुधार का क्रम देखा जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिन भर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 289 के अंक पर दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा खराब श्रेणी में रखी जाती है। एक दिन पहले वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में थी। हवा में घुले-मिले दोनों मुख्य प्रदूषक कणों की मात्रा में भी एक दिन पहले की तुलना में कमी आई है। शाम 6 बजे हवा में पीएम 10 कणों की मात्रा 210.3 और पीएम 2.5 की मात्रा 128.9 रही। तीन दिनों तक वायु गुणवत्ता खराब और बेहद खराब श्रेणी के बीच रहने का अनुमान है।

News item/letter/article/editorial Published on 04.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi) ✓
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

मौसम का मिजाज: जनवरी के महीने में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखे विविध रंग H4

अमेरिका ठंड से ठिठुरा तो ऑस्ट्रेलिया गर्मी में तपा

नई दिल्ली | हिटी

नए साल की शुरुआत में विभिन्न देशों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अत्यधिक ठंडा रहा और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी पड़ी।

आल्प्स और हिमालय की चोटियों में जनवरी माह में पहले से ज्यादा बर्फबारी हुई। भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हिमपात हुआ।

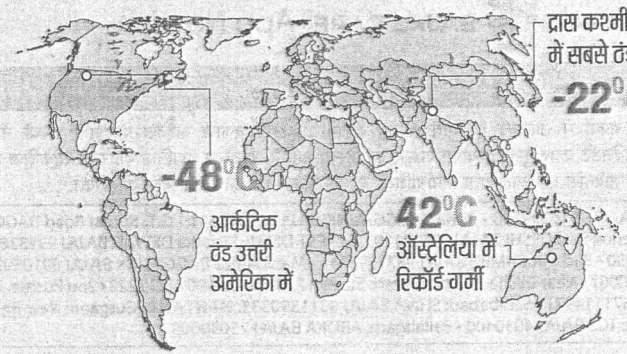

उत्तरी अमेरिका में 24 मरे : उत्तरी अमेरिका में भयंकर ठंड का प्रकोप रहा। भारी हिमपात होने के कारण करीब 24 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग गंभीर बीमार हो गए।

गर्मी और बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल

ऑस्ट्रेलिया में साल की शुरुआत से ही जनवरी माह में भयंकर गर्मी का प्रकोप रहा। 24 जनवरी का सबसे ज्यादा गर्म रहा। इस दौरान 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्वी ऑस्टेलियाई राज्य क्वींसलैंड में बाढ़ आ गई। इसके कारण पूरा इलाके और लोगों के घरों में पानी भर गया।

News item/letter/article/editorial Published on 03.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Namami Gange moves in slow motion

Of ₹2,300 cr allotted in 2018–19, only ₹700 cr has been used

SHREYA JAI
New Delhi, 2 February

The Centre and Prime Minister Narendra Modi, who represents Varanasi in the Lok Sabha, had made cleaning up of the Ganga a key poll promise in 2014. But over this fiscal year, only one-third of the funds allotted for the project has been utilised so far.

According to the Revised Estimates 2018-19 in the interim Union Budget for 2019-20 presented in Parliament on Friday, Namami Gange was allotted ₹2,300 crore. Of this, only ₹700 crore has been utilised.

Namami Gange was launched in 2014. Several initiatives were planned such as sewage treatment, cleaning of the river surface and ghats, redevelopment of the riverfront and conservation of biodiversity.

The funds were allotted to states through which the river passes: Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. As many as 261 projects were announced, but only 76 have been concluded. The total expenditure till date is ₹5,979 crore — barely 23 per cent of the ₹25,000-crore allocation.

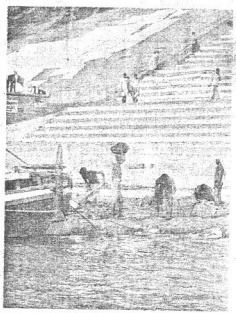

PROJECTS UNDER THE SCHEME

	Number	Completed	Sanctioned amount (₹ cr)	Current expenditure (₹ cr)
Sewage infrastructure	137	31	20,033	3,934
Ghat/river surface cleaning/river front development	64	31	1,242	790
Non-infra institutional development	18	1	1,086	42
Research & study	5	1	126	6.97
Biodiversity	6	2	33.42	21
Afforestation/ecological task force/bioremidation/ construction of toilets	31	10	1,426.26	1,020
			23,946.68	5,813.97

All data till December 2018

Source: Namami Gange portal

Government officials said the number of sanctioned projects was "very high". The mechanism to award the contract was complex.

"Some of the projects are to be implemented by the central government, some by the state governments, and a few by private players. These have to be awarded through a proper contract process," said a senior official.

The official said private players such as Essel Infra, Shapoorji Pallonji, and Adani Enterprises have been awarded six cities by the Centre. The remaining 80 are supposed to be bid out by the state agencies.

The Ministry of Water Resources is headed by Nitin Gadkari, also in-charge of inland waterways. A section of the Ganga is National Waterways Number 1. The government has allotted another ₹700 crore for the next financial year. It has also tried to raise money from private players and public donations.

Recently, the government auctioned gifts received by the PM, and the funds from these will be added to the Clean Ganga Fund (CGF).

But, this is not the first time that the slow utilisation of funds to clean up the Ganga has come to light. The Comptroller and Auditor General o India in a 2017 report also flagged this off

"A corpus of ₹198.14 crore (as of 3 March 2017) was available in the CGF However, Namami Gange could no utilise any amount out of the CGF," the CAG observed. Some sewage treatment projects are funded by the World Bank as well.

"There are close to 25 projects under the hybrid-annuity model awarded under public-private partnership (PPP) with an estimated investment of $1 billion. The government would give 40 per cent capital cost and the balance would be given as annuity over the period of project depending on the performance. The fund requirement is less in this," said a senior official.

Officials also said the fund availability for the projects is sufficient for the next two years and all the projects will be completed by 2020.

Sewage treatment is the largest project component under Namami Gange, with an allocation of ₹20,000 crore.

Utilisation, however, is only 20 per cent. Bharatiya Janata Party-led Uttar Pradesh has got the most (₹8,515 crore for 43 projects). Utilisation is dismal at 22 per cent.

News item/letter/article/editorial Published on 03.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi) ✓
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Treated water can nurse wetlands back to health, say experts

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Even as water tables drop around most parts of the world, recharging groundwater aquifers naturally could still be done effectively in Delhi and other parts of the country by simply maintaining and rejuvenating the lost wetlands, experts observed on Saturday — on the occasion of World Wetlands Day. Hundreds of scholars, scientists and conservationists were in attendance at Delhi's Yamuna Biodiversity Park (YBP), where successful revival of waterbodies has occurred in the past. Other locations in Delhi too saw a good response, with experts highlighting the need for their preservation.

"The idea is to educate children, researchers and nature enthusiasts about the importance of these wetlands. In NCR, not only are they hubs for migratory and local birds but are also natural ways to recharge the groundwater tables. A healthy wetland draws all sorts of wildlife as well," said Faiyaz Khudsar, scientist in-charge at YBP.

Professor CR Babu, head of Centre for Environmental Management of Degraded Ecosystems, said that Delhi's Neela Hauz Biodiversity Park presents the ideal model for a fully restored and functional wetland. "We have showcased how a constructed wetland model can be successfully carried out by using water from an STP," said Babu.

Hundreds of scholars, scientists and conservationists came together on World Wetlands Day at Yamuna Biodiversity Park

Dr Govind Singh, associated with "Delhi Greens", who has been studying Delhi's groundwater levels, says the city is undergoing extreme stress at moment in terms of water extraction. Dr Rajiv Kumar, vice chairman at Niti Aayog, said wetland conservation efforts adopted in the country so far had a limited impact due to silo like approaches that failed to build on convergence opportunities.

According to data, wetlands hold close to 5% of freshwater in India. As per Global Wetlands Outlook, between 1970 and 2015, inland and marine/coastal wetlands both declined by approximately 35%, three times the rate of forest loss. Experts, however, said that birds can also be an ideal indicator of habitat with migratory species still arriving in large numbers this winter. "Places like YBP in Delhi have recorded a significant increase in the number of migratory birds in its wetlands, including Red-crested pochards," said Khudsar.

News item/letter/article/editorial Published on 03.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi) ✓
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Govt's grand plan to clean up Yamuna: Ask babas, kids to spread the good word

Recycling Of Dumped Puja Items And Stopping Of Agriculture On Floodplain Proposed

Ritam.Halder@timesgroup.com

New Delhi: Meeting with religious leaders to make them aware of water pollution, awareness campaigns for schoolchildren, roping in NGOs for collection points for puja items to recycle these into incense sticks are some of the steps planned by the Delhi government to stop pollution in Yamuna.

In a recent meeting of the two-member Yamuna pollution monitoring committee appointed by National Green Tribunal, deputy chief minister Manish Sisodia agreed on an awareness campaign against agriculture on the Yamuna floodplain and by "dissuading people from eating such produce as it leads to entry of toxins in the food chain".

Enforcement action against sale of such vegetables on the Yamuna bridges across the city will also be taken up by the municipal corporations.

NGT in January 2015 had prohibited farming on Yamuna banks, saying, "It is an established fact that presently, vegetables, fodder grown and allied projects at the floodplain of the river are highly contaminated. Besides containing ingredients of high pollutants, such produce is even found to contain metallic pollutants."

In a report submitted to the green court this month, the panel of B S Sajwan and former Delhi chief secretary Shailaja Chandra said, "The committee explained (to the Delhi government) how there was an urgent need to start awareness campaigns about the pollution in the drains, waterbodies and Yamuna, which affects the quality of life of citizens adversely. The monitoring committee requested the deputy CM to start campaigns to build public awareness at the school-level, which can be expanded to cover all organised and unorganised colonies as a comprehensive approach to stopping pollution and also rejuvenating the waterbodies, outfall drains and the river."

Sisodia suggested a meeting with leaders of all faiths who could convey messages about how households and colonies contribute to pollution and how that could be avoided.

"The environment and forest department was asked to convene a meeting with religious leaders on the urgent need to combat water pollution caused by human activity which was choking the drains... The deputy chief minister asked the director of education to plan an awareness campaign for schoolchildren and in particular to organise a painting competition on the banks of the Yamuna to enable children to internalise the message of cleanliness starting with the home but ending with a clean, flowing river," the report said.

The government will use prominent NGOs to set up collection points at Wazirabad, ISBT, Signature Bridge and Nizamuddin Bridge that are today being used to throw puja items into the river. Efforts to convert the retrieved waste into agarbattis and other useful products will be made. Receptacles for puja items will be specially provided at the entries to the bridges.

The committee has also suggested that the government should set up a consortium of NGOs and board members of DPCC to jointly consider and approve projects that can curb pollution and utilise waste.

Steps planned by Delhi govt to stop pollution in Yamuna

MEETING WITH RELIGIOUS HEADS
To convey messages on how households and, eventually, residential colonies contribute to pollution

ROPING IN SCHOOL KIDS
Director of education to plan awareness campaign for schoolchildren; organise painting competition on Yamuna banks

NGOs
To set up collection points at Wazirabad, ISBT, Signature Bridge and Nizamuddin Bridge

OTHERS

- Convert retrieved waste into agarbattis and other useful products
- Use special puja material receptacles
- Consider innovative projects to reduce pollution by utilise puja remnants, plastic waste and other recyclable waste material retrieved from Yamuna
- Organise public awareness campaigns to discourage agriculture on floodplain; enforce ban on sale of vegetables near river

Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

2019 BEGINS IN EXTREMES

Frostbite inducing cold in America, severe heat in Australia and heavy snowfall in the Alps and the Himalayas marked an unusually extreme January, the World Meteorological Organisation has said

THE COLD

IN NORTH AMERICA

■ Dangerous cold and heavy snow crippled the northern US this week, killing more than two dozen people and frostbite, broken bones, heart attacks and carbon monoxide poisoning leaving hundreds injured

■ The cold was caused by an influx of Arctic air, with wind chill factors making temperatures outdoors as cold as -53.9°C in southern Minnesota, which can cause frostbite — the condition in which tissues freeze — within minutes

■ The frigid winds were a result of a mix of climatic conditions, all of which are being seen by experts as a consequence of climate change.

HIMALAYAS AND ALPS HIT TOO

■ Indian weather officials issued warnings of heavy or very heavy rain and snow for Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, prompting warnings of avalanches amid an intense cold wave.

■ In the European Alps, some regions witnessed record snowfall in January. In Hochfilzen, in the Tirol region of Austria, more than 451cm of snow fell in the first 15 days of January, an event statistically only expected once a century

DELHI's LONG WINTER

■ With snow in the mountains and a series of western disturbances hitting northwest India, Delhi recorded the longest cold spell in at least 13 years

HEATWAVES AND FIRES

IN AUSTRALIA

■ Temperatures hit a record with a series of heatwaves unprecedented in their scale and duration gripping the country. The city of Adelaide saw an unprecedented high of 46.6°C on January 24. In the eastern Australian state of Queensland, once-in-a-century floods covered cities in waist-deep waters with more heavy rain predicted to make the situation worse.

IN SOUTH AMERICA

■ A weather station in the capital Santiago set a new record of 38.3°C on January 26, while central parts of Chile saw maximums topping 40°C

Coldest February morning for Delhi in five years

News item/letter/article/editorial Published on 03.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi) ✓

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

RP-3

गोमा से खूब खाया-कमाया, काम आधा भी नहीं हो पाया

प्रवर्तन निदेशालय और एनजीटी की कवायद से निर्मल होगी गोमती!

31 मई तक नदी साफ न हुई तो नपेंगे अफसर

ईडी की जांच की आंच अखिलेश-शिवपाल तक

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

महेन्द्र प्रताप सिंह
patrika.com

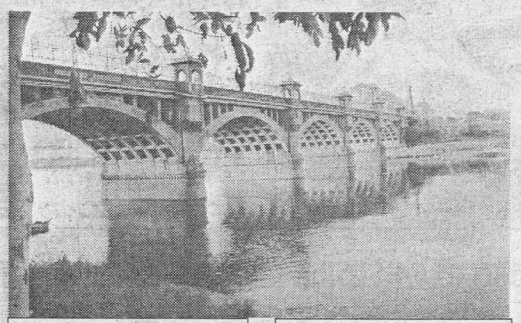

लखनऊ . स्वच्छ शहर का तमगा पाने में भले ही राजधानी लखनऊ इन्दौर से पिछड़ गया हो लेकिन लखनऊ की जीवन दायिनी गोमती नदी के निर्मल होने की उम्मीदें जगीं हैं। सब कुछ ठीक रहा तो न केवल गोमती की धारा स्वच्छ हो सकेगी बल्कि इसके घाटों की सुन्दरता भी बढ़ेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 31 मार्च तक तक गोमती की सफाई पर रिपोर्ट तलब की है। उधर, गोमती के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी तेज कर दी है।

लखनऊ को देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा मिलने में संदेह है लेकिन, गोमती नदी निर्मल हो सकेगी, इसकी उम्मीदें बढ़ी हैं। एनजीटी ने सदानीरा गोमती नदी के प्रदूषण और इसके काले पानी पर योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि गोमती एक्शन प्लान, नमामि गंगे और गोमती रिवर फ्रंट जैसी अनेक परियोजनाओं और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गोमती की गंदगी कम क्यों नहीं हुई। एनजीटी की पहल बनी एक समिति गोमती की बदहाली की जांच करेगी। इस समिति में तीन जज और एक पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हैं।जल निगम के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में ही गोमती में हर रोज 720 लाख लीटर सीवर और गंदा पानी मिल रहा है। इसमें से सिर्फ 400 लाख लीटर ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में से होकर गोमती में पहुंचता है। यानी हर रोज 320 लाख लीटर गंदगी गोमती में मिल रही है।

रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में तेजी और गोमती नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए एनजीटी द्वारा उठाए गए कदमों से उम्मीद जगी है कि गोमती सदानीरा बन सकेगी।

31 मार्च तक रिपोर्ट

एनजीटी गोमती की सफाई पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, वन विभाग और जल निगम से जवाब मांगा है। 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गोमती की सफाई पर एक्शन प्लान सौंपना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीपी सिंह पूरे मामले की निगरानी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मई तक गोमती पूरी तरह से साफ नहीं हुई तो एनजीटी जिम्मेदारों को तलब भी करेगी।

जुटाए जा रहे तथ्य

गोमती नदी के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच में तेजी आई है। इससे उम्मीद बनी है कि गोमती की निर्मलता के साथ ही इसकी सुंदरता में भी इजाफा होगा। अखिलेश सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के लिए ईडी ने छापेमारी तेज कर दी है। तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही गोमती सफाई के नाम पर बंदरबांट करने वाले सलाखों के अंदर होंगे। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल पर शिकंजा कस सकता है।

क्या है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला

अखिलेश यादव की सरकार में लखनऊ में गोमती नदी के सुंदरीकरण का काम शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के बीचोंबीच बहने वाली गोमती नदी के 13 किलोमीटर लंबे किनारों का सौंदर्यीकरण किया जाना था। पहले यह प्रोजेक्ट 550 करोड़ का था फिर 656 करोड़ का हो गया, जो बाद में बढकर 1513 करोड़ तक पहुंच गया। योगी सरकार का आरोप है कि इस रकम का 95 फीसद यानी 1437 करोड़ खर्च होने के बावजूद सिर्फ 60 फीसद काम पूरा हो सका। योगी सरकार द्वारा गठित आलोक सिंह आयोग ने अपनी जांच में रिवर फ्रंट में गड़बड़ियां पाई थीं। इसी आधार पर पुलिस ने 19 जून, 2017 को गोमती नगर थाने में सिंचाई विभाग के 7 अभियंताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई और 30 नवम्बर, 2017 को सीबीआई ने भ्रष्टाचार साहित अनेक धाराओं में केस दर्ज कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने रिवर फ्रंट घोटाले में इसी हफ्तेलखनऊ के 5 ठिकानों के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, राजस्थान के भिवांडी और हरियाणा के फरीदाबाद में भी 4 जगह छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। इनमें लखनऊ में विशालखंड में ठेकेदार अखिलेश सिंह के यहां छापा पड़ा। अखिलेश सिंह संतकबीर नगर के मेहंदावल से बीजेपी विधायक राकेश सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं। गैमन इंडिया में भी छापे पड़े। गैमन इंडिया गोमती रिवर फ्रंट की मुख्य निर्माण कंपनी है। इसके अलावा राजाजीपुरम और गोमतीनगर के 2 और ठिकाने भी खंगाले गए। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। आठ इंजीनियरों पर मामले दर्ज हैं।इस घोटाले की आंच तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और शिवपाल यादव के करीबी रूप सिंह यादव पर भी शिकंजा कस सकता है। गलत तरीके टेंडर दिए गए। कमिशन की लालच में प्रॉजेक्ट की लागत बढ़ायी गयी। इसके लिए मनमाने तरीके से टेंडर बांटे गए। डायफॉम वॉल की ऊंचाई 14 फुट से बढ़ाकर 16.5 और बाद में 18 फुट तक कर दी गई। ठेकेदारों को टेंडर की तारीख निकलने के बाद टेंडर दिए गए। निर्माण से जुड़े फंड को बिना आदेश के डायवर्ट किया गया। ठेकेदारों को तय लागत से ज्यादा का भुगतान किया गया। ठेकेदारों के जरिए इंजीनियरों को कमीशन मिला।

News item/letter/article/editorial Published on 02.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman ✓
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Govt projects 10 focus areas

PTI
NEW DELHI, 1 FEBRUARY 8T-2

Unveiling the development vision for the next decade, the government on Friday said it would focus on 10 key areas including job creation, physical and social infrastructure building, pollution-free nation and clean rivers.

Presenting the Budget 2019-20, Finance Minister Piyush Goyal laid out vision for 10 most important dimensions in 2030.

"The first dimension of this vision will be to build physical as well as social infrastructure for a USD 10-trillion economy and to provide ease of living," he said.

It will comprise, he said, next-generation infrastructure of roads, railways, seaports, airports, urban transport, gas and electric transmission and inland waterways. On the social infrastructure side, Goyal said every family will have a roof over its head and will live in a healthy, clean and wholesome environment.

"We will also build a quality, science-oriented educational system with institutes of excellence providing leadership at the top," he said. The other dimensions of the visions include creating a Digital India reaching every sector of the economy; making India a pollution-free nation; expanding rural industrialisation using modern digital technologies to generate massive employment; space; and clean rivers.

Elaborating on rural industrialisation, he said this would be built upon the Make in India approach to develop grassroot-level clusters, structures and mechanisms encompassing the MSMEs, village industries and start-ups spread in the country.

The fifth dimension of the Vision for India 2030 is clean rivers, with safe drinking water to all Indians and efficient use of water in irrigation using micro-irrigation techniques.

"Our coastline and our ocean waters powering India's development and growth is the sixth dimension of our vision," he said, adding that making India self-sufficient in food, exporting to the world to meet their food needs and producing food in the most organic way is the eighth dimension.

"High farm production and productivity will be achieved through modern agricultural practices and value addition. An integrated approach towards agro and food processing, preservation, packaging and maintenance of the cold chain will be our focus of attention," he added.

News item/letter/article/editorial Published on 02.02.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath

Haribhumi, Delhi

'आगरा में नहीं थमा प्रदूषण, 25 करोड़ रुपये जमा करे सरकार'

एनजीटी ने जोशी, एनजीओ सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एवं इनवायरनमेंट की अर्जी पर यह निर्देश दिया

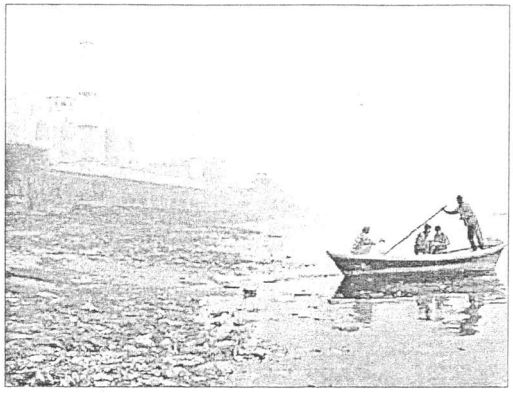

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि आगरा में यमुना में कूड़ा और सीवेज डालकर बड़ा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने को लेकर 25करोड़ रुपये की परफार्मेंस गारंटी जमा करे।

एनजीटी ने कहा कि आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर सड़कों पर यूं ही ठोस अपशिष्ट जलाया जा रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नालों के जाम रहने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। उसने कहा कि सीवर प्रणाली का 50 फीसद हिस्सा काम नहीं कर रहा है, अशोधित सीवेज खुली नालियों में डाला जा रहा है और निकास व्यवस्था 55 साल पुरानी हो गई है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को यह राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि इस मामले पर आगे चलकर विचार किया जाएगा तबतक यह एक अंतरिम व्यवस्था है।

दोषी अफसरों, प्रदूषकों पर कार्रवाई करने की है छूट

पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को दोषी अधिकारियों और प्रदूषकों का उत्तरदायित्व तय करने तथा उनके

- छावनी रेलवे स्टेशन की सड़कों पर जलाया जा रहा है ठोस अपशिष्ट
- जगह-जगह कूड़े के ढेर हैं, नालों के जाम रहने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है

विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने की छूट है। राज्य का संबंधित प्रशासन कानून के अनुसार चिह्नित प्रदूषकों से उपयुक्त मुआवजा हासिल करने के लिए कदम उठा सकता है और तीन महीने के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट ईमेल के मार्फत दे सकता है।

यूपी के मुख्य सचिव 12 मार्च को मामले पर दें रिपोर्ट

अधिकरण ने यूपी के मुख्य सचिव को 12 मार्च को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह (मुख्य सचिव) स्वयं को चीजों से अवगत करने, प्रगति पर निगरानी रखने एवं निजी सुनवाई के दौरान रिपोर्ट देने के लिए संबंधित व्यक्तियों की बैठक बुला सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह की अगुवाई वाली निगरानी समिति की प्रगति रिपोर्ट भी दे सकते हैं। अधिकरण ने आगरा के निवासी डी के जोशी और एनजीओ सोशल एक्शन फार फारेस्ट एवं इनवायरनमेंट की अर्जी पर यह निर्देश दिया।